

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम०के०सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 7058-एक/2015 - विरुद्ध- आदेश दिनांक 21-9-2015 - पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल - प्रकरण क्रमांक 601/2012-13 अपील

श्रीमती अर्चना पत्नि अंतेश कुमार
ग्राम मौरोदा, हाल निवास त्योंदा रोड
गंज बासोदा जिला विदिशा म०प्र०

---अपीलांट

विरुद्ध

म०प्र०शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प
जिला विदिशा, मध्य प्रदेश

---रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री बी०एन०मिश्रा)
(रिस्पाण्डेन्ट अनुपस्थित)

आ दे श

(आज दिनांक 9 -12-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 601/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-9-2015 के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47 (क) 5 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोश यह है कि अपीलांट ने ओम प्रकाश चौरसिया पुत्र रामगोपाल चौरसिया से भूमि सर्वे क्रमांक 154/2 रकबा 0.410 हैक्टर करा करने का अनुबंध किया तथा दिनांक 16-12-11 को अनुबन्ध पत्र स्टाम्प रूपये 86,500/- लेकर उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया। उप पंजीयक द्वारा उपरोक्त भूमि पर स्थगन होना बताते हुये विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया, जिसके कारण विक्रय विलेख का पंजीयन नहीं हो सका। अपीलांट द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला विदिशा से स्टाम्प

MM

Pa

रुपये 86,500/- की राशि रिफण्ड करने की माँग की। कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला विदिशा ने प्रकरण क्रमांक 40 सी-132/2011-12 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 31-10-2012 पारित करके स्टाम्प की राशि रिफण्ड योग्य न मानते हुये प्रकरण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलांत ने आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त भोपाल संभाग ने प्रकरण क्रमांक 53/12-13 अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग को दिनांक 15-4-13 को निराकरण हेतु अंतरित किया, जिस पर से अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण क्रमांक 601/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-9-2015 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से दुखी होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांत के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। रिस्पाण्डेन्ट पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

4/ अपीलांत के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपीलांत ने ओम प्रकाश चौरसिया पुत्र रामगोपाल चौरसिया से भूमि सर्वे क्रमांक 154/2 रकबा 0.410 हैक्टर कय करने का अनुबंध किया तथा दिनांक 16-12-11 को अनुबंध पत्र स्टाम्प रुपये 86,500/- लेकर उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया। उप पंजीयक द्वारा उपरोक्त भूमि पर स्थगन होना बताते हुये विकय विलेख निष्पादित नहीं किया, जिसके कारण विकय विलेख का पंजीयन नहीं हो सका। इस प्रकार अपीलांत द्वारा कय किये गये स्टाम्प अनुपयोगी हो गये। जब अपीलांत द्वारा 16-12-2011 को निष्पादित दस्तावेज के स्टाम्प वापिसी हेतु दिनांक 13-3-12 को आवेदन प्रस्तुत किया, कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला विदिशा ने प्रकरण क्रमांक 40 सी-132/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 31-10-2012 से स्टाम्प की राशि रिफण्ड योग्य न मानते हुये प्रकरण निरस्त कर दिया। विचार योग्य है कि क्या अपीलांत द्वारा कय किये गये स्टाम्प की राशि नियमानुसार वापिसी योग्य है ? भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 50 इस प्रकार है :-

50. धारा 49 के अधीन राहत किये जाने के लिये आवेदन कब दिया जायेगा-





धारा 49 के अधीन राहत दिये जाने के लिये आवेदन निम्नलिखित कालावधियों के भीतर अर्थात् -

- (1) खंड (घ)(5) में वर्णित मामलों में लिखित की तारीख से दो मास के भीतर
- (2) किसी ऐसे स्टाम्पित कागज के मामले में जिस पर उसके किसी पक्षकार द्वारा कोई भी लिखित निष्पादित नहीं की गई है, स्टाम्प के खराब हो जाने के छह माह के भीतर
- (3) किसी ऐसे स्टाम्पित कागज के मामले में, जिस पर उसके पक्षकारों में से किसी के द्वारा कोई लिखित निष्पादित की गई है, लिखित की तारीख के छह मास के भीतर या यदि उस पर तारीख नहीं है तब ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा वह प्रथम बार या अकेले ही निष्पादित की गई थी, उसके निष्पादित किये जाने के छह मास के भीतर किया जाएगा।

जब भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 50 में उपरोक्तानुसार व्यवस्था दी गई है, अपीलांत महिला है एवं पर्दानसीन महिला होना बताया गया है, की परिस्थितियों पर कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला विदिशा ने एवं अपर आयुक्त, भोपाल संभाग ने ध्यान न देने में भूल की है, जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 601/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-9-2015 एवं कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 40 सी-132/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 31-10-2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं अपीलांत द्वारा कय किये गये स्टाम्प की राशि 86,500/-रूपये वापिस किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर